भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2565
मंगलवार, 19 दिसंबर, 2023/28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण

†2565. श्री भर्तृहरि महताबः
श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री छेदी पासवानः
श्री रवि किशनः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत किए गए प्रायोगिक परीक्षण सफल रहे हैं और यदि हां, तो लाभार्थी पीएसीएस और इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएसीएस परियोजनाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2023-24 के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, पीएसीएस-वार कितना बजट आबंटन किया गया है और मंत्रालय द्वारा इसके लिए विभिन्न राज्यों को अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) मंत्रालय की पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण परियोजना किस प्रकार सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी, कार्य कुशलता में वृद्धि करेगी तथा पीएसीएस को सुदृढ़ और सशक्त बनाएगी;

(घ) राज्यों में उक्त योजना के अंतर्गत शामिल पीएसीएस की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसके कार्यान्वयन से सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में नई आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त पीएसीएस से जुड़े किसानों को क्या-क्या विभिन्न लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (च): भारत सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को सशक्त करने के लिए 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अनुमोदित की गई है, जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय

सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है । इस परियोजना के कुल बजट 2,516 करोड़ रुपए में से भारत सरकार, राज्य सरकार और नाबार्ड की हिस्सेदारी क्रमश: 1528 करोड़ रुपए, 736 करोड़ रूपए और 252 करोड़ रुपए है ।

अब तक 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 62,318 पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 475.55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के हिस्से का प्रस्तावित संशोधित अनुमान 350 करोड़ रुपए है, जिसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों एवं नाबार्ड को पूर्व में जारी निधि के उपयोग के पश्चात् उन्हें जारी किया जा सकता है । स्वीकृत पैक्स की संख्या और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अभी तक जारी भारत सरकार के हिस्से की राशि का ब्यौरा **अनुलग्नक** पर संलग्न है ।

नाबार्ड द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा चुका है और अब तक 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 5,673 पैक्स में ईआरपी परीक्षण आरंभ हो चुका है । राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद और लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण के कार्य प्रक्रियाधीन हैं ।

इस परियोजना के अधीन पैक्स स्तर पर कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के कार्यान्वयन से पैक्स के शासन और पारदर्शिता में सुधार आएगा, जिसके फलस्वरूप ऋणों को त्वरित संवितरण, लेनदेन लागत में कमी, भुगतान के असंतुलनों में कमी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन और कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी । इससे किसानों के बीच पैक्स के कार्यकरण के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देगी ।

पैक्स कंप्यूटरीकरण की परियोजना, पैक्स के लिए आदर्श उपविधियों के अधीन विनिर्दिष्ट सभी आर्थिक गतिविधयों के लिए एक समग्र ईआरपी समाधान प्रदान करेंगे जिसमें अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋणों के लिए वित्तीय सेवाओं, प्रापण विकल्पों, सार्वजनिक वितरण की दुकानों (PDS) का प्रचालन, व्यवसाय नियोजन, भांडागारण, क्रय-विक्रय, उधार, आस्ति प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, इत्यादि जैसे विभिन्न मॉड्यूल होंगे ।

यह परियोजना अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋणों तक किसानों की सुगम पहुंच में सुधार लाएगी । इसके अतिरिक्त, कंप्यूटरीकरण से पैक्स की आदर्श उप-नियमों के अधीन वर्णित विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के लिए विभिन्न मॉड्यूलों के समावेश द्वारा किसानों को पैक्स स्तर पर ही ये सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी । यह पैक्स के आर्थिक कार्यकलापों के विवधिकरण में भी सहायक होगा, जिसके परिणामस्वरूप किसान सदस्य आय के अतिरिक्त और संवहनीय स्रोत प्राप्त कर सकेंगे ।

*****

अनुलग्नक

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत पैक्स की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जारी भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रुपए)
1	आंध्र प्रदेश	2037	14.93
2	अरुणाचल प्रदेश	14	0.21
3	असम	583	6.41
4	बिहार	4495	32.95
5	छत्तीसगढ़	2028	14.86
6	गोवा	58	0.32
7	हरियाणा	711	4.85
8	हिमाचल प्रदेश	870	13.22
9	झारखंड	1500	10.99
10	कर्नाटक	5491	40.25
11	मध्य प्रदेश	4534	33.23
12	महाराष्ट्र	12000	87.95
13	मणिपुर	232	2.55
14	मेघालय	112	1.23
15	मिजोरम	25	0.27
16	नागालैंड	33	0.50
17	पंजाब	3482	25.52
18	राजस्थान	5585	43.81
19	सिक्किम	107	1.63
20	तमिल नाडु	4532	33.2
21	त्रिपुरा	268	2.95
22	उत्तर प्रदेश	3062	24.68
23	पश्चिम बंगाल	4167	30.54
24	गुजरात	5754	42.17
25	जम्मू और कश्मीर	537	5.25
26	पुड्डुचेरी	45	0.44
27	अंडमान और निकोबार	46	0.52
28	लद्दाख	10	0.12
कुल		**62,318**	**475.55**